

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259105
SG-DL-E-05122024-259105असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 281
No. 315]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946	[N. C. T. D. No. 281

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधी न्याय और विधायी कार्य विभाग

आदेश

दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

दिल्ली न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा भत्ते आदेश, 2024

फा. सं.1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—जबकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 643/2015, जिसका शीर्षक "अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य" है, में दिनांक 09 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि जस्टिस पी. वी. रेड्डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग जिला न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उपयुक्त संशोधन के लिए सिफारिशें देने के उद्देश्य से गठित किया गया।

और जबकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 27 जुलाई, 2022 और 19 मई, 2023 के निर्णयों के माध्यम से द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के संशोधन की सिफारिशों को स्वीकार किया है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्च

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संशोधन के संबंध में उपयुक्त नियम बनाकर /संशोधित कर वेतन और पेंशन को संशोधित कर दिया है।

और जबकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय 21 भत्तों के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित निर्देश जारी किए हैं।

अतः, 4 जनवरी, 2024 के निर्णय में जारी निर्देशों के अनुपालन में, और सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय की जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति द्वारा 21 भत्तों में से 6 भत्तों के स्पष्टीकरण / व्याख्यात्मक ज्ञापन के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार न्यायिक अधिकारियों (जिनमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं) को देय /प्रतिपूर्ति योग्य निम्नलिखित भत्तों को मंजूरी देने में प्रसन्नता व्यक्त करती है।

1. समवर्ती प्रभार भत्ता (Concurrent Charge Allowance)

(i) समवर्ती प्रभार भत्ता एक न्यायिक अधिकारी को उस स्थिति में देय होगा जब वह अधिकारी किसी अतिरिक्त न्यायालय/पद का प्रभार संभालता है या एक माह में दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए उसका कार्य करता है।

(ii) समवर्ती प्रभार भत्ता उस अतिरिक्त पद के वेतनमान (मूलवेतन) के न्यूनतम का 8% की दर से देय होगा, जब न्यायिक अधिकारी एक माह में 10 से अधिक और 15 कार्य दिवसों तक किसी अतिरिक्त न्यायालय/पद का प्रभार संभालता है या उसका कार्य करता है; और 15 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायालय/पद का प्रभार संभालने या कार्य करने पर यह भत्ता उस अतिरिक्त पद के वेतनमान (मूलवेतन) के न्यूनतम का 10% की दर से देय होगा। हालांकि, यदि अतिरिक्त पद का वेतनमान उस पद से अधिक है जो न्यायिक अधिकारी वर्तमान में धारण कर रहे हैं, तो उन्हें समवर्ती प्रभार भत्ता उस मूल वेतन पर गणना कर देय होगा जो उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।

(iii) समवर्ती प्रभार भत्ता उस स्थिति में देय होगा जब न्यायिक अधिकारी ने अतिरिक्त न्यायालय/पद के लिए, सबूत/बयानों की रिकॉर्डिंग, विविध आवेदन या जमानत आवेदन का निपटारा (केवल स्थगन प्रदान करने या सामान्य आदेश पारित करने के बजाय) जैसे न्यायिक कार्य किए हों या दैनिक आधार पर अतिरिक्त न्यायालय/पद का पर्याप्त प्रशासनिक कार्य संभाला हो। न्यायिक अधिकारी को यह भत्ता प्राप्त करनेके लिए किए गए कार्य का एक संक्षिप्त विवरण संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तुत करना होगा और यह भत्ता संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर देय होगा।

(iv) यदि कोई न्यायिक अधिकारी एक से अधिक अतिरिक्त न्यायालय/पद का प्रभार संभालता है या उसका कार्य करता है, तो उसे किसी अतिरिक्त भुगतान का अधिकार नहीं होगा।

हालांकि, यदि न्यायिक अधिकारी विभिन्न दिनों में (अर्थात् एक ही दिन में एक से अधिक न्यायालय का कार्य करने के बजाय) एक से अधिक अतिरिक्त न्यायालय/पद का प्रभार संभालता है या कार्य करता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भत्ता प्राप्त करने का पात्र है, उन दिनों की संचयी संख्या और संचयी कार्य को ध्यान में रखा जाएगा।

2. आवागमन/परिवहन भत्ता (Conveyance/Transport Allowance):

(i) न्यायिक अधिकारी जो आधिकारिक गाड़ियाँ उपयोग करते हैं, उन्हें बिना किसी शुल्क के निजी उपयोग के लिए प्रतिमाह 300 किलोमीटर तक उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) कार खरीदने के लिए न्यायिक अधिकारियों को रु.10 लाख तक के सॉफ्ट लोन की सुविधा 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दी जाएगी। लोन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और आवेदन की तारीख से एक महीने के भीतर लोन राशि जारी कर दी जाएगी।*

(iii) उपरोक्त सॉफ्ट लोन सुविधा उन न्यायिक अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिन्होंने किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से अपने नाम पर कार लोन लिया हुआ है और इस सॉफ्ट लोन सुविधा में स्थानांतरित होना चाहते हैं, बशर्ते ऐसे अधिकारी उस समय सॉफ्ट लोन सुविधा के लिए पात्र थे, जब उन्होंने बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से कार लोन लिया था। संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सॉफ्ट लोन सुविधा की राशि उस लोन तक सीमित हो, जिसे न्यायिक अधिकारी द्वारा अभी चुकाया जाना बाकी है, लेकिन अधिकतम रु.10 लाख तक।

सॉफ्ट लोन स्वीकृत होने पर यह राशि पात्र न्यायिक अधिकारी को एक मुश्त जारी की जाएगी, और न्यायिक अधिकारी को लोन राशि जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर सॉफ्ट लोन उपयोग प्रमाणपत्र (**Soft Loan Utilization Certificate**) प्रस्तुत करना होगा।

* (नोट: दिल्ली न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा कार खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन सुविधा (अग्रिम) के लिए दिशा-निर्देश/प्रविधियाँ शीघ्र जारी की जाएँगी।)

3. गृह सहायक/घरेलू सहायता भत्ता (Home Orderly/Domestic Help Allowance):

जिला न्यायाधीश, सुपर टाइम स्केल (Super Time Scale) के न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने वर्तमान नीति (जो दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित है) के अनुसार दो गृह सहायक नियुक्त किए हैं, वे उनके द्वारा नियुक्त एक अकुशल कर्मी के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे, जो **01.01.2016** से न्यूनतम **₹.10,000/-** प्रतिमाह है। जहां तक उनके द्वारा नियुक्त दूसरे अकुशल कर्मी का संबंध है, उन्हें **01.01.2016** से दिल्ली में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के **50%** की दर से प्रतिपूर्ति मिलती रहेगी।

4. एयर कंडीशनर भत्ता:

(i) कैप कार्यालय भत्ता/फर्नीचर अनुदान के अतिरिक्त, न्यायिक अधिकारी हर 5 वर्ष में एक एयर कंडीशनर की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, अर्थात् 2016-2020 के ब्लॉक वर्ष, 2021-2025 के ब्लॉक वर्ष, और इसी प्रकार आगे।

(ii) एयर कंडीशनर की लागत की प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा **₹.50,000/-** प्लस लागू जीएसटी होगी, जो संबंधित ब्लॉक वर्ष के लिए मान्य होगी।

(iii) ब्लॉक वर्ष 2021-2025 के लिए एक एयर कंडीशनर की लागत की प्रतिपूर्ति एक वैध बिल के आधार पर की जाएगी, जो किसी जीएसटी पंजीकृत डीलर या ऑनलाइन माध्यम से 01.01.2021 के बाद और 31.12.2025 से पहले खरीदा गया हो।

(iv) ब्लॉक वर्ष 2016-2020 के लिए एक एयर कंडीशनर की लागत की प्रतिपूर्ति स्व-प्रमाणन के आधार पर की जाएगी, जिसमें यह शर्त होगी कि न्यायिक अधिकारी द्वारा 01.01.2016 के बाद और इस ज्ञापन के जारी होने से पहले वास्तव में एक एयर कंडीशनर खरीदा गया हो।

(v) यदि न्यायिक अधिकारी का जीवनसाथी भी न्यायिक सेवा (या किसी अन्य सरकारी सेवा जिसमें ऐसा भत्ता अनुमेय हो) में है, तो दोनों अलग-अलग इस भत्ता/प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

(vi) फर्नीचर की अवधारण से संबंधित प्रचलित प्रक्रिया ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एयर कंडीशनर के संबंध में भी जारी रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायिक अधिकारी जिन्होंने ब्लॉक वर्ष 2021-2025 या ब्लॉक वर्ष 2016-2020 के लिए एयर कंडीशनर खरीदा है, वे ब्लॉक वर्ष 2026-2030 के लिए 01.01.2026 को एयर कंडीशनर खरीदने के लिए पात्र हो जाएंगे, भले ही उन्होंने पिछले ब्लॉक वर्षों के लिए इसे कब खरीदा हो।

5. एल.टी.सी/एच.टी.सी (LTC/HTC):

(i) न्यायिक अधिकारियों को तीन वर्षों के एक ब्लॉक में एक एलटीसी और एक एचटीसी लेने की अनुमति दी जाएगी, इस प्रतिबंध के साथ कि दोनों एलटीसी और एचटीसी एक ही वर्ष में नहीं लिया जा सकता।

(ii) एलटीसी/एचटीसी के दावे के लिए ब्लॉक वर्ष 2016-2018; 2019-2021; 2022-2024; 2025-2027 और आगे के रूप में माने जाएंगे।

(iii) प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन होगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस (इसके कार्यालय/काउंटर, वेबसाइट या मोबाइल ऐप से) या सरकार द्वारा अधिकृत एजेंटों से खरीदे गए हों।

(iv) एलटीसी/एचटीसी/एचटीसी रूपांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी अन्य निर्देश, "परिवर्तित रूप में लागू" न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगे।

6. गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance):

गृह निर्माण अग्रिम (HBA)* न्यायिक अधिकारियों के लिए एक निजी व्यक्ति से तैयार घर खरीदने हेतु गृह निर्माण अग्रिम नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध होगी, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ:

(i) विक्रेता (विक्रेताओं) के पास उसके नाम पर पंजीकृत विक्रय विलेख (Conveyance Deed), बिक्री विलेख (Sale Deed), या पट्टा विलेख (Lease Deed) होना चाहिए।

(ii) सभी मौद्रिक लेन-देन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होना चाहिए।

(iii) जहां उचित हो, संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरकारी प्राधिकरणों की सहायता से घर का बाजार मूल्य जांच सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिक्री का मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

* (नोट: दिल्ली न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के दिशा-निर्देश/प्रविधियाँ शीघ्र जारी की जाएँगी।)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 29th November, 2024

DELHI JUDICIAL SERVICE AND DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE ALLOWANCES ORDER, 2024

F. No.1/16/2020-Judl./P.F.2/Suptlaw/2085.—WHEREAS, The Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi in W.P.(Civil) No. 643/2015 titled as All India Judges Association vs. Union of India &Ors., vide its Order dated 09th May, 2017 directed appointment of Second National Judicial Pay Commission under the Chairmanship of Mr. Justice P. V. Reddi, former Judge of Supreme Court of India for the purpose of making suitable recommendations for revision of Pay, Allowances and Other conditions of Service of members of the District Judiciary;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 27th July, 2022 and 19th May, 2023 had accepted the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission qua revision of pay and pension of the Judicial Officers and accordingly Government of NCT of Delhi after receipt of necessary concurrence from Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, has already revised pay and pension by suitably framing/amending relevant rules in respect of revision of pay, pension and other retirement benefits of the Officers of the Delhi Judicial Service And Delhi Higher Judicial Service;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India vide its Judgment dated 4th January, 2024 has issued directions with respect to the allowances (21 in number) payable to the Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Family Pensioners as recommended by the Second National Judicial Pay Commission;

NOW THEREFORE, in due compliance with the directions issued vide Judgment dated 4th January, 2024, after receipt of necessary concurrence from the competent authority, the Government of NCT of Delhi, on the basis of the explanatory/clarificatory memorandum in respect of 6 allowances out of the 21 allowances, issued by Committee for Service Conditions of the District Judiciary, High Court of Delhi, is pleased to sanction following allowances which shall be payable/reimbursable to the Judicial Officers (including those who are on deputation), namely:-

1. Concurrent Charge Allowance

- (i) *Concurrent Charge allowance shall be paid to a judicial officer where such officer holds charge of/does the work of an additional Court/post beyond a period of ten working days in a month.*
- (ii) *Concurrent Charge allowance shall be admissible at the rate of 8% of the minimum of the pay scale of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds charge of/does the work of an additional Court/post for more than 10 and up to 15 working days in a month; and at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post (basic pay) where the judicial officer holds charge of/does the work of an additional Court/post for more than 15 working days in a month. However, in case the pay scale of the additional post is higher than the pay scale of the post which the judicial officer is currently holding, he will be entitled to Concurrent Charge allowance calculated at such basic pay not exceeding the current basic pay drawn by the officer.*
- (iii) *Concurrent Charge Allowance shall be admissible so long as, the judicial officer has done some judicial work in the nature of recording of evidence/statements, disposal of miscellaneous applications or bail applications, etc. (as opposed to merely granting adjournments or passing routine orders) or has handled substantial administrative work, on a daily basis, of the additional Court/post. The judicial officer shall submit a brief summary of the work done (of the additional court/post) to the concerned Principal District & Sessions Judge while making a request for claiming such allowance and the allowance shall be payable on the orders of the concerned Principal District & Sessions Judge.*
- (iv) *A Judicial Officer shall not be entitled to any additional payment in case he holds the charge of/does the work of, more than one additional Court/Post.*
However, in case the Judicial Officer holds the charge of/does the work of more than one additional Court/post on different days (as opposed to doing the work of more than one Court on the same day) the cumulative number of days on which he has worked; and otherwise also the cumulative work done by him, shall be taken into account while considering his request for claiming such allowance.

2. Conveyance/Transport Allowance:

- (i) *The judicial officers using official cars shall be permitted to use them for private purposes to the extent of 300 kms per month without the payment of any charges.*
- (ii) *Soft Loan facilities* to the extent of Rs. 10 Lakhs for the purchase of car shall be extended to the judicial officers on simple interest at the rate of 4% per annum. The loan process shall be simplified and the loan amount shall be disbursed within one month from the date of application.*
- (iii) *The aforesaid soft loan facility* shall also be available to a judicial officer who has already availed a car loan in his own name from any other bank or financial institution and wants to migrate to this facility of soft loan, provided such officer was eligible for grant of soft loan facility on the date when he/she obtained the car loan from the bank or other financial institution. The concerned Principal District & Session Judge shall ensure that such soft loan facility is limited to the amount of loan still due to be repaid by the judicial officer subject to a maximum of Rs. 10 Lakhs. On sanction of the soft loan, such amount shall be released to the eligible judicial officer in one lump sum and the judicial officer shall produce the Soft Loan Utilization Certification within one month of the date of release of the loan amount.*

3. Home Orderly/Domestic Help Allowance

The Judicial Officers in District Judge, Super Time Scale, who had engaged two Home Orderlies in accordance with the current policy (as approved by the Government of NCT of Delhi), shall, in respect of one unskilled worker employed by them, be entitled for reimbursement of minimum wages as notified in the NCT of Delhi, subject to a minimum of Rs.10,000/- per month with effect from 01.01.2016. In so far as the second unskilled worker employed by them is concerned, they shall continue to avail reimbursement at the rate of 50% of the minimum wages as notified in the NCT of Delhi, with effect from 01.01.2016.

** Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course.*

4. Air Conditioner Allowance:

(i) In addition to camp office allowance/furniture grant, the Judicial Officers shall also be entitled for reimbursement of the cost of one air conditioner once in 5 years i.e. for the Block year 2016-2020, Block year 2021-2025 and so on.

(ii) *The upper limit regarding reimbursement of the cost of air conditioner shall be Rs. 50,000/- plus applicable GST in a given block year.*

(iii) *The reimbursement of the cost of one air conditioner for the Block Year 2021-2025 shall be made on production of a valid bill of purchase of the air conditioner from any dealer having GST registration or through online mode, on or after 01.01.2021 but not later than 31.12.2025.*

(iv) *The reimbursement of the cost of one air conditioner towards the Block Year 2016-2020 shall be on self-certification basis without the requirement of production of any bill in case one air conditioner has actually been purchased by the judicial officer on or after 01.01.2016 but prior to the issuance of this memorandum.*

(v) *In case the spouse of the judicial officer is also in judicial service (or other government service where such allowance is admissible) both of them shall be entitled to separately claim such allowance/reimbursement.*

(vi) *The prevalent practice in respect of retention of furniture shall continue in respect of Air Conditioners also after expiry of the block period. It is clarified that the judicial officers who have purchased air conditioners for the Block Year 2021-2025 or the Block Year 2016-2020 shall become eligible for purchase of air conditioner for the Block Year 2026-2030 on 01.01.2026 irrespective of the date of purchase of the same for the previous block years.*

5. L.T.C/H.T.C:

- (i) *The judicial officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of three years, with the restriction that both LTC and HTC cannot be availed during the same year.*
- (ii) *For the purpose of claiming L.T.C/H.T.C, the block years be taken as 2016-2018; 2019-2021; 2022-2024; 2025-2027 and so on.*
- (iii) *The reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines (from its physical office/counter or from its website or from its mobile application) or from the agents authorized by the Government.*

** Guidelines/Modalities for Soft Loan Facility (Advance) for purchase of Car by Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course.*

- (iv) *All other instructions issued by the Central Government with respect to LTC/HTC/HTC conversion shall apply, mutatis mutandis, to the judicial officers as well.*

6. House Building Advance:

House Building Advance (HBA) shall be available to judicial officers for the purchase of a ready built house from private individuals also in terms of the House Building Advance Rules, 2017 subject to the following additional conditions: -*

- (i) *the seller(s) should have a registered conveyance deed or sale deed or lease deed in his/their favour;*
- (ii) *all monetary transactions should be through banking channels;*
- (iii) *wherever deemed appropriate, the Principal District & Sessions Judge(s) may get the market value of the house assessed with the assistance of such government authorities as deemed appropriate so as to ascertain as to whether the sale consideration has been inflated or not.*

** Guidelines/Modalities for House Building Advance (HBA) for Officers of Delhi Judicial Service and Delhi Higher Judicial Service shall be issued in due course.*

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)